भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या:5602
04अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

भविष्य की वैश्विक महामारियों के लिए आपातकालीन चिकित्सा अवसंरचना

†5602. श्री पुट्टा महेश कुमारः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में विगत वैश्विक महामारी के कारण हुए भारी आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए कोई आपातकालीन नीति तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) भविष्य की संभावित वैश्विक महामारियों के लिए भारत की चिकित्सा और आपातकालीन अवसंरचना की तैयारियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) भविष्य की वैश्विक महामारी की स्थितियों के लिए भारत को तैयार करने हेतु नियुक्त किए गए/वर्तमान में कार्यशील कुल शोधकर्ताओं और पेशेवरों की संख्या कितनी है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान, विशेषकर आंध्र प्रदेश सहित देशभर में संभावित वैश्विक महामारियों के लिए हमारे चिकित्सा अवसंरचना को तैयार करने के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार कुल कितनी निधि आवंटित और उपयोग की गई है; और

(ङ) क्या सरकार ने आम जनता के बीच वैश्विक महामारी की तैयारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई अभियान चलाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): भारत सरकार ने महामारी के मद्देनजर आर्थिक विकास पर निरंतर जोर देने के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को सुदृढ़ करके एक समावेशी नीति वाला दृष्टिकोण अपनाया है। सरकार कम आय वाले और कमजोर वर्गों को राहत प्रदान करने के लिए विभिन्न लक्षित क्रियाकलापों जैसे बुजुर्गों को पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाएं और बुजुर्गों के अनुकूल सार्वजनिक स्थान और गतिशीलता विकल्प को लागू कर रही है। इसके साथ ही, किफायती आवास, श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, वित्तीय समावेशन, बुनियादी सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए सरकार के प्रयास समग्र आरोग्य में सुधार करते हैं। साथ ही, सरकार बेहतर पूंजीगत व्यय, अवसंरचना निर्माण, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, व्यापार करने में आसानी, कृषि, शिक्षा, कौशल विकास, लघु और सूक्ष्म उद्यम और शहरी विकास पर ध्यान देकर भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की उच्च विकास दर को बनाए रखने की संभावना है। इन उपायों से भारतीय अर्थव्यवस्था को 2021-22 से 2024-25 के दौरान 8.2 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर हासिल करने में मदद मिली है (2024-25 के लिए अनुमान सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी दूसरा अग्रिम अनुमान है)।

(ख): महामारियों की रोकथाम और उनके प्रति तैयारी साझा वैश्विक जिम्मेदारी है। देश में भविष्य की महामारियों/सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के प्रति बेहतर तैयारी के लिए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए अपेक्षित सहायता प्रदान करता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों की स्थापना और चिकित्सा कर्मियों की भर्ती सहित जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

साथ ही, भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलावा देश के सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं:

- प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए जन स्वास्थ्य और अन्य स्वास्थ्य सुधारों में निवेश बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। इसके तहत i) रोगों का शीघ्र पता लगाने के लिए गांवों और शहरों में स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों को सुदृढ़ बनाना; ii) जिला स्तर के अस्पतालों में नए गहन परिचर्या संबंधी बिस्तरों को जोड़ना; iii) 11 उच्च फोकस वाले राज्यों में ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू) के लिए सहयोग; और iv) सभी जिलों में एकीकृत जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित करना।

- पंद्रहवें वित्त आयोग ने स्वास्थ्य क्षेत्र के विशिष्ट घटकों के लिए स्थानीय सरकारों के माध्यम से अनुदान की सिफारिश की है और जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच साल की अवधि में अनुदान देने की सिफारिश की है।

- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) का उद्देश्य किफायती विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाकेंद्रों को बढ़ाना है। इस योजना के दो घटक हैं, अर्थात् (i) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना; और (ii) मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों (जीएमसीआई) का उन्नयन।

- केंद्र प्रायोजित योजना 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के तहत, वंचित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों, जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है, को प्राथमिकता देते है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि साझाकरण पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में और अन्य के लिए 60:40 है।

(ग): महामारी के प्रति तैयारी और अनुक्रिया एक बहुआयामी क्रियाकलाप है जिसमें अनुसंधान और विकास गतिविधियों में रोग महामारी विज्ञान, जीनोमिक्स, निदान, दवाओं और टीकों जैसे महामारी के प्रतिकार हेतु विकास और नैदानिक परीक्षण, सामान आदि सहित क्रियाकलापों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। भारत सरकार स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय सहित कई तकनीकी मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से ऐसी क्रियाकलापों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देती है।

(घ): महामारी जैसी जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों के कारण किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने, प्रयोगशाला नेटवर्क का विस्तार, निगरानी, चिकित्सा सामानों की खरीद आदि के लिए भारत कोविड-19 आपातकालीन अनुक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज (ईसीआरपी-I) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 8473.73 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। भारत कोविड-19 आपातकालीन अनुक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज-चरण II के अंतर्गत, स्वास्थ्य अवसंरचना को बढ़ाने और चिकित्सा सामानों के प्रावधान के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 12,740.22 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में बिस्तर क्षमता बढ़ाने, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) संयंत्रों की स्थापना, बाल चिकित्सा उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना और बाल चिकित्सा आईसीयू बिस्तरों आदि के लिए प्रदान की गई धनराशि भी शामिल थी।

इसके अलावा, मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में क्रिटिकल केयर ब्लॉकों, एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं आदि के माध्यम से बेहतर जन स्वास्थ्य तैयारियों के लिए पीएम-एबीएचआईएम (वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 तक) के तहत केंद्रीय अनुदान के रूप में लगभग 4500.64 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

ईसीआरपी-I, ईसीआरपी-II और पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सरकार को क्रमशः 441.94 करोड़ रुपये 417.91 करोड़ रुपये और 80.86 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

(ङ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र योजना, स्वस्थ नागरिक अभियान (एसएनए) का उद्देश्य सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) क्रियाकलापों के माध्यम से सभी आयु वर्ग के लोगों के स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना और उनके आरोग्य को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कार्यक्रम के तहत बीमारियों की प्राथमिकताओं के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ऐसी आईईसी क्रियाकलाप किए जाते हैं। आईईसी क्रियाकलापों ने लोगों में स्वास्थ्य चाहने वाले व्यवहार को प्रोत्साहित किया है , जिसके परिणामस्वरूप सरकार के विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य परिणाम सामने आए हैं।

*****